(c) what steps Government propose to prevail upon other States to emulate such States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) Yes Sir. In his inaugural address to the Power Ministers' Conference held on 8th and 9th January, 1993, the Finance Minister had urged that the minimum tariff for supply of power to the agricultural sector should be fixed at 60 paise per unit. The Conference, however, decided that the minimum agricultural traiff may be levied at 50 paise per unit for the present, for implementation by all States by the end of March, 1993. So far, 10 States and one Union Territory have reportedly adopted the minimum agricultural traiff of 50 paise per unit while the remaining States have resolved to implement it as per an Action Plan, adopted in the above Conference.

गुजरात की विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन न किया जाना

157. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि गैस आपूर्ति प्राप्त करने और भूमि का अधिग्रहण करने में प्रक्रिया सम्बन्धी उलझनों तथा मशीनों के उपलब्ध न होने के कारण गुजरात की विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं की कमी के कारण कौन-कौन सी परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में फिजूलखर्ची की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू : (क) से (ङ) ईंधन सप्लाई और मशीनरी की उपलब्धता से सम्बन्धित समस्याओं के फलस्वरूप गुजरात की कुछेक विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है । भूमि अधिग्रहण के कारण, ऐसा बताया गया है कि किसी भी परियोजना में विलम्ब नहीं हुआ है । जिन परियोजनाओं के मामले में विलम्ब हुआ है उनमें कुछ लिग्नाइट विस्तार, सिक्का विस्तार चरण-दो, उत्राण संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (सी. सी.पी.पी.) तथा कवास, सी.सी.पी.पी. शामिल हैं ।

राज्य सरकार और विद्युत मंत्रालय इन परियोजनाओं के कार्य की सघन मानिटरिंग कर कर रहे हैं तथा कमियों को दूर करने के लिए अपेक्षित कदम उठा रहे हैं ।

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड का अनुसंधान एवं विकास सत्र

158. **श्री सोमपाल** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1992 में जयपुर में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड का चार दिवसीय अनुसंधान एवं विकास सत्र आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस सत्र में विद्युत उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और विद्युत आपूर्ति को सुप्रवाही बनाने के सम्बन्ध में क्या-क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) सरकार इन सुझावों का किस प्रकार से उपयोग करने का इरादा रखती है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां ।